

भारत की मौद्रिक नीति के सयंत्रों का बैंकिंग क्षेत्र पर प्रभाव

Snehlata

Department of Commerce

Maharishi Dayanand University, Rohtak

सार :

बैंकिंग क्षेत्र भारत का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। यह सकल घरेलू उत्पाद की ओर करीब 7.7% योगदान देता है। मौद्रिक नीति के उपकरणों के कार्यन्वयन से बैंकिंग क्षेत्र पर गहरा प्रभाव पड़ता है। इस पेपर में बैंकिंग क्षेत्र पर पड़ने वाले प्रभाव के बारे में बताया गया है।

मुख्य शब्द : बैंकिंग, मौद्रिक, संस्थान, ऋणदाता, राष्ट्रीकरण, वित्तीय

भूमिका :

भारत देश के बैंकिंग क्षेत्र में केंद्रीय बैंक का बहुत अधिक महत्व है। रिजर्व बैंक एक केंद्रीय बैंक है, और इसे अंतिम ऋणदाता भी कहते हैं। 17वीं शताब्दी में जो केंद्रीय बैंक के रूप में जिस संस्थान की पहचान की गई थी उसकी पहचान स्वीडिस रिस्क बैंक के संयुक्त स्टॉक बैंक रूप में हुई।

रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भारत का केंद्रीय बैंक है। इस बैंक की स्थापना हिल्टन यंग कमीशन की सिफारिशों के आधार पर 1 अप्रैल 1935 ई० को हुई। स्वतंत्रता के बाद 1949 ई० में रिजर्व बैंक का राष्ट्रीकरण कर दिया गया। रिजर्व बैंक देश की मौद्रिक नीति के निर्माण में सरकार को सलाह देता है, देश के आर्थिक विकास के लिए वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करने का प्रबंध करता है। देश में कीमत स्थिरता, बचत व निवेश को बढ़ाना, आर्थिक विकास को बढ़ावा देना और बेरोजगारी को दूर करने का प्रयत्न करता है। मुद्रा की पूर्ति और मुद्रा की लागत की दर को नियंत्रित करता है। बैंकिंग सिस्टम को नियमित करता है। संक्षेप में, रिजर्व बैंक विकासात्मक तथा बैंकिंग दोनों प्रकार के कार्य करता है।

मौद्रिक नीति के अंतर्गत साख नियंत्रण के लिए सयंत्र निम्नलिखित है। जैसे – बैंक दर, नकद कोष अनुपात, रेपो दर, रिवर्स रेपो दर, वैधानिक तरलता अनुपात और खुले बाजार की प्रक्रियाएँ आदि।

(A)

1.1 रेपो दर (Repo Rate) –

एक ऐसी ब्याज दर जिस पर व्यापारिक बैंक रिजर्व बैंक से उधार ले सकता है। इसकी स्थापना दिसंबर 1992 में की गई। और रेपो रेट को छूट की दर भी कहा जाता है। और पॉलिसी दर भी कहा जाता है।

1.2 रिवर्स रेपो दर (Reverse Repo Rate) –

ये दर रेपो रेट से बिल्कुल विपरीत है। यह एक ऐसी ब्याज दर है जिस पर रिजर्व बैंक व्यापारिक बैंकों द्वारा रिजर्व बैंक में जमा की गई राशि पर देता है और रिवर्स रेपो रेट की स्थापना नवंबर 1996 में की गई। रिवर्स रेपो रेट बाजार तरलता को कम करती है। रेपो दर और रिवर्स रेपो दर को सरलता समायोजन की सुविधा भी कहते हैं।

वर्तमान रेपो दर– 5.15 % (2020), 17 March

वर्तमान रिवर्स रेपो दर– 4.90 % (2019), March

पिछले 5 वर्षों के लिए भारत में ऐतिहासिक रेपो दर बनाम रिवर्स रेपो दर की पद्धति निम्न प्रकार से है—

Impact of Banking Sector 2016 to 2019 on the bank's Repo Rate & Reverse Repo Rate in Indian Banks

Table - 1

Date	Repo Rate	Reverse Repo Rate
17 March 2019	5.15 %	4.90
1 August 2018	6.50 %	6.25
6 April 2017	6.25 %	6.00
4 October 2016	6.25 %	5.75

(Table – 1)तालिका एक—इस तालिका से पता चलता है कि कितना प्रतिशत परिवर्तन हुआ है। रेपो दर और रिवर्स रेपो दर में, इसमें पिछले 4 साल का डाटा लिया हुआ है। 2016 से 2019 तक का डाटा लिया गया है, और उसमें रेपो रेट और रिवर्स रेपो दर में परिवर्तन हुआ है। 2016 में रेपो दर 6.25 प्रतिशत है। लेकिन वर्तमान (2019)रेपो दर 5.15 प्रतिशत है। यानी कि पहले से कम रेपो दर है और रिवर्स रेपो दर 2016 में 5.75 प्रतिशत थी, वर्तमान रिवर्स रेपो दर 4.90 प्रतिशत है। 5.75 प्रतिशत से कम होकर 4.90 प्रतिशत हो गया।

इससे बैंकों पर और अर्थव्यवस्था पर प्रभाव पड़ा, क्योंकि रेपो दर के कम होने से बैंक सस्ती दर से उधार ले सकते हैं। और इससे अर्थव्यवस्था पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। और इसी प्रकार रिवर्स रेपो दर के कम होने से भी बैंकों पर प्रभाव पड़ा। इसके कारण बैंक अब मुद्रा बाजार में भी निवेश कर सकते हैं। और अर्थव्यवस्था में तरलता को बढ़ाता है, जिससे अर्थव्यवस्था का आर्थिक विकास होता है।

Importance of Repo Rate & Reverse Repo Rate

1. **तरलता विनियम** :- वाणिज्यिक बैंकों की शीघ्र तरलता की कमी को दूर करने के लिए कई प्रकार से सरलता, सुगमता प्रदान की जाती है। रेपो दर से तरलता संकट का बचाव किया जा सकता है। रेपो दर भारतीय बैंकिंग प्रणाली में तरलता को इंजेक्ट करते हैं। रिवर्स रेपो दर तरलता को अवशोषित करते हैं।
2. **मुद्रास्फीति नियंत्रण** :- रिजर्व बैंक रेपो दर और रिवर्स रेपो दर को अच्छे से नियंत्रण करके या उनका अच्छे से प्रबंध करके मुद्रास्फीति पर नियंत्रण कर सकती है, क्योंकि बहुत अतिरिक्त पैसा होने के कारण भी मुद्रास्फीति बढ़ने से कीमत ज्यादा हो जाती है। जिसके कारण आर्थिक विकास पर बुरा प्रभाव पड़ता है। निवेश तथा बचत पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। विदेशी निवेश पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है। अगर मुद्रास्फीति पर नियंत्रण न किया जाए तो बैंकिंग पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि अगर मुद्रास्फीति बढ़ेगी तो लोन की दर भी बढ़ जाएगी। जिसके कारण होम लोन की ब्याज दर भी बढ़ जाएगी। तरलता में कभी भी मंदी हो सकती है। यह भी बुरा प्रभाव डालती है।

Effect on increasing Repo Rate & Reverse Repo Rate by RBI on Banking Sector or Economy

- (A) 1. रेपो दर में वृद्धि से बैंकिंग क्षेत्र और अर्थव्यवस्था पर बहुत प्रभाव पड़ता है।
- i. वाणिज्यिक बैंकों से कर्ज लेना महंगा हो जाता है।
 - ii. कर्जों की दरों में वृद्धि हो जाती है।
 - iii. जब ऋणों की दर बढ़ती है तो इससे बैंकों पर बुरा असर पड़ता है और आर्थिक विकास पर भी ऋणात्मक प्रभाव पड़ता है।
 - iv. रेपो दर बढ़ने से साख का संकुचन होता है। क्योंकि बैंकों को आरबीआई से अधिक ब्याज दर पर वित्त उपलब्ध होगा।
 - v. रेपो रेट में वृद्धि अर्थव्यवस्था की वृद्धि को धीमा कर देता है।
 - vi. रेपो दर बढ़ जाने के कारण बैंकों को ज्यादा ब्याज देना पड़ेगा। अगर आरबीआई ब्याज दर चार्ज करेगी वैसे ही दूसरे बैंक ब्याज दर चार्ज करेंगे। अगर रेपो रेट में वृद्धि होगी तो बाजार ब्याज दर भी बढ़ेगा और जिसके कारण आर्थिक विकास नहीं हो पाता।
 - vii. अगर किसी देश में महंगाई की दर बढ़ती है तो रिजर्व बैंक का गवर्नर निर्णय लेता है कि महंगाई बढ़ गई है। लोगों के पास पैसा ज्यादा हो तो आरबीआई ने निर्णय लिया कि रेपो रेट को बढ़ा दिया जाए। मुद्रास्फीति के उच्च स्तर के दौरान, आरबीआई अर्थव्यवस्था में धन के प्रवाह को नीचे लाने के प्रयास करता है। रेपो दरमें वृद्धि करना एक ऐसा तरीका है, जिससे मुद्रास्फीति को नियमित कर सकते हैं।
 - viii. उच्च रेपो दर अर्थव्यवस्था को धीमा करती है।

- ix. रेपो दर में वृद्धि के कारण छोटी अवधि में धन की लागत बढ़ जाती है।
2. रिवर्स रेपो दर के बढ़ने से साख में कमी होती है क्योंकि वाणिज्य बैंक अधिक ब्याज कमाने की इच्छा से RBI के पास धन जमा करवाते हैं। इससे बैंकों की ऋण देने की क्षमता कम हो जाती है। रिवर्स रेपो दर में वृद्धि से अभिप्रायः जब बैंकों के पास अत्यधिक मात्रा में फंड है तो रिजर्व बैंक रिवर्स रेपो दर को बढ़ा सकता है। रिवर्स रेपो दर बढ़ने से बैंकों पर और अर्थव्यवस्था पर भी प्रभाव पड़ता है।
- i. रिवर्स रेपो दर बढ़ने से बैंकों के लिए निवेश का सुरक्षित विकल्प है। निवेश को प्रोत्साहन मिलता है और जिसके कारण बचत को बढ़ावा मिलता है। अर्थव्यवस्था पर अनुकूल प्रभाव पड़ता है।
- ii. बैंकों के लिए निवेश इसलिए है क्योंकि रिवर्स रेपो दर में बैंकों का ऋण देने की बजाय आरबीआई के पास जमा किया जाता है।

Effect of decreasing Repo Rate & Reverse Repo Rate by RBI on Banking Sector and Economy

(B)

- i. रेपो दर में कमी – जब रिजर्व बैंक रेपो दर में कमी करता है तो इससे बैंकिंग क्षेत्र पर प्रभाव पड़ता है। क्योंकि वह सस्ती दर पर उधार ले सकता है और उपभोक्ता उधार ले सकता है क्योंकि ऋण पर ब्याज दर भी कम है जिसके कारण आर्थिक विकास पर प्रभाव पड़ा।
- ii. रिवर्स रेपो रेट में कमी :- रिजर्व बैंक द्वारा जब रिवर्स रेपो दर में कमी की जाती है तो इससे बैंकिंग क्षेत्र पर प्रभाव पड़ता है क्योंकि यह बैंकों को मनी मार्केट में पैसा निवेश करने की ओर अग्रसर करता है। जिसके कारण बचत को बढ़ावा मिलता है और तरलता में भी वृद्धि होती है। अर्थव्यवस्था पर भी अच्छा प्रभाव पड़ता है।

1.3 नकद अनुपात (Cash Reserve Ratio) :-

रिजर्व बैंक व्यापारिक बैंकों के नकद अनुपात कोष को नियंत्रित करता है। व्यापारिक बैंकों को नकद कोष अनुपात का पालन करना जरूरी है। बैंक सम्पूर्ण राशि जमा को नकदी के रूप में आरबीआई के पास रखता है। जब रिजर्व बैंक इस अनुपात को बढ़ा दे तो व्यापारिक बैंकों के पास ऋण देने के साधन कम हो जाते हैं और साख का संकुचन होता है और अगर रिजर्व बैंक इस अनुपात को कम कर दे तो इससे बैंकों के पास ऋण देने के साधन अधिक हो जाते हैं और साख का संकुचन होता है।

1.4 वैधानिक तरलता अनुपात (Statutory Liquidity Ratio) :-

इसमें बैंक अपनी जमा राशि का कुछ प्रतिशत तरलता के रूप में रखता है। इस जमा राशि को अपने पास रखता है, अगर Reserve Bank इस वैधानिक तरलता अनुपात को बढ़ा दे तो बैंकों के पास ऋण के साधन कम हो जाते हैं। अगर इस अनुपात को कम करा दिया जाए तो ऋण के साधन अधिक हो जाएंगे। $CRR + SLR = \text{Reserve Ratio}$

वर्तमान नकद कोष अनुपात= 4 % (2019)

वर्तमान वैधानिक तरलता अनुपात= 18.25 % (2019)

पिछले 4 वर्षों के लिए भारत में ऐतिहासिक नकद कोष अनुपात और वैधानिक तरलता अनुपात दर की प्रवृत्ति निम्नलिखित है—

Impact of Banking Sector 2016 to 2019 on the Bank Cash Reserve Ratio and Statutory liquidity Ratio in Indian Banks.

Date	Cash Reverse Ratio	Statutory Liquidity Ratio
March 2019	4 %	19.5 %
August 2018	4 %	19.5 %
April 2017	4 %	20.5 %
October 2016	4 %	20.75 %

(Table – 2) तालिका – 2 इस तालिका से पता चलता है कि नकद कोष अनुपात और वैधानिक तरलता अनुपात में कितना प्रतिशत परिवर्तन हुआ है। इसमें 4 साल का डाटा लिया हुआ है। 2016 से 2019 तक, अक्टूबर 2016 में नकद कोष अनुपात 4 प्रतिशत है। और वर्तमान में 4 प्रतिशत है। कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ। लेकिन वैधानिक तरलता में परिवर्तन हुआ है 2016 में वैधानिक तरलता अनुपात 20.75 प्रतिशत है लेकिन वर्तमान में (2019) 18.25 प्रतिशत है। पहले से कम हो गया। जिससे साख का विस्तार होगा। तो अर्थव्यवस्था पर इसका अनुकूल प्रभाव पड़ेगा।

Effect of increasing or decreasing statutory liquidity ratio by RBI on Banking Sector and economy.

जब रिजर्व बैंक वैधानिक तरलता अनुपात में कमी करता है तो इससे बैंकों पर प्रभाव पड़ता है। और अर्थव्यवस्था पर भी प्रभाव पड़ता है क्योंकि अगर वैधानिक तरलता अनुपात को कम कर दिया जाता है तो बैंकों के पास ऋण देने की अधिक साधन उपलब्ध होते हैं। तो इससे आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलता है। निवेश को भी बढ़ावा मिलता है। जिसके कारण अर्थव्यवस्था पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है।

जब रिजर्व बैंक वैधानिक तरलता अनुपात में वृद्धि करती है तो इससे भी बैंकों और अर्थव्यवस्था पर प्रभाव पड़ता है अगर वैधानिक तरलता अनुपात में वृद्धि कर दी जाए तो बैंकों के पास ऋण देने के कम साधन हो जाएंगे। जिसके कारण लोग निवेश भी नहीं कर पाएंगे ना ही बचत को बढ़ावा मिलेगा और जिसके कारण अर्थव्यवस्था पर बुरा असर पड़ता है इस लिए वैधानिक तरलता अनुपात के घटने या बढ़ने का असर बैंकिंग और अर्थव्यवस्था पर पड़ता है।

Effect of increasing or decreasing CRR by the RBI on banking and economy.

जब रिजर्व बैंक द्वारा नकद कोष अनुपात घटाया बढ़ाया जाता है तो इसका असर बैंकिंग प्रणाली और अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। जैसे – जब रिजर्व बैंक नकद कोष अनुपात में कमी करता है तो इससे बैंकों के पास ऋण देने के साधन ज्यादा मात्रा में होते हैं, तो इसके कारण एक अनुसूचित वाणिज्यिक

बैंकों के पास देश भर में उधारकर्ताओं को व्यक्तिगत ऋण देने की क्षमता होती है और जिसके कारण नकद प्रवाह को बढ़ावा मिलेगा। और बैंकों के पास अन्य व्यवसायों में निवेश करने के लिए अधिक पैसा होगा। क्योंकि नकद कोष अनुपात से शेड्यूल्ड कर्माचारियों बैंक्स अपनी तरलता को बनाए रख सकते हैं। जिसके कारण बैंकों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है और अर्थव्यवस्था में विकास होता है।

जब रिजर्व बैंक द्वारा नकद कोष अनुपात में वृद्धि की जाती है तो इसका भी बैंकों और अर्थव्यवस्था पर प्रभाव पड़ता है।

Impact on Banking Sector 2016 to 2019 on the Banks Repo Rate or Reverse Repo Rate, Cash Reserve Ratio or Statutory liquidity ratio in Indian Banks.

Table - 3

Date	RePo Rate	Reverse Rate	CRR	SLR
2016	6.25 %	5.75 %	4 %	20.75 %
2017	6.25 %	6.00 %	4 %	20.5 %
2018	6.50 %	6.25 %	4 %	19.5 %
2019	5.15 %	4.90 %	4 %	19.5 %

इस तालिका द्वारा दर्शाया गया है कि क्या प्रभाव पड़ा है। बैंकिंग क्षेत्र में रेपो दर, रिवर्स रेपो दर, नकद कोष अनुपात और वैधानिक तरलता अनुपात में परिवर्तन की वजह से क्या फर्क पड़ा सारणी-3 में बताया गया है। इसमें 5 साल का डाटा लिया गया है। 2016 से 2020 तक। अगर इस Table में देखा जाए तो रेपो दर 2016 में 6.25 है और जो कि कम होकर 2020 में 5.15 % है और रिवर्स रेपो दर 2016 में 5.75 % है जो कि वर्तमान में घटकर 4.90 % होगी और नकद कोष अनुपात भी 2016 से 2019 तक 4 % ही है। इसमें कोई परिवर्तन नहीं आया। लेकिन वैधानिक तरलता अनुपात 2016 में 20.75 या वर्तमान 2019 में कम होकर 18.25% हो गया। इन दरों के कम होने से बैंकों के पास ज्यादा ऋण देने के साधन उपलब्ध होते हैं। जिससे साख का विस्तार होता है और अर्थव्यवस्था पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है।

निष्कर्ष :-

जब रिजर्व बैंक नकद कोष अनुपात और वैधानिक तरलता अनुपात को कम करता है तो इससे बैंकों के पास ज्यादा ऋण देने के साधन उपलब्ध होते हैं। और रिवर्स रेपो दर कम होने पर साख का निर्माण होता है और इन सबकी दर बढ़ने पर साख का संकुचन होता है। लेकिन बैंको को नकद कोष अनुपात, वैधानिक तरलता अनुपात, रेपो दर और रिवर्स रेपो दर की दरों को ना ही अधिक मात्रा में बढ़ाना चाहिए ना ही अधिक मात्रा में कम करना चाहिए। इसे एक सीमा तक ही घटाया या बढ़ाया जाना चाहिए। अगर अधिक दरे होंगी तो जनता के पास धन की कमी हो जाएगी। जिससे देश के विकास में बाधाएं उत्पन्न होंगी और यदि दरें अधिक कम हो जाए तो जनता के पास अधिक पैसा होगा। जिससे मुद्रास्फीति आ जाएगी। जिसके कारण बैंको को दौबारा दरें बढ़ानी पड़ेंगी इस लिए इन दरों में संतुलन

बनाकर रखना आवश्यक है। अतः इन सब मात्रात्मक तकनीकों का अध्ययन करने के बाद पता चलता है कि इन सभी सयंत्रों का बैंकिंग और अर्थव्यवस्था पर अपने-अपने सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव पड़ते हैं।

संदर्भ :-

1. <https://www.My loan Care.in>
2. <https://www.Proptiger.com> 7 Post
3. <https://www.Bankbazar.com>
4. <https://www.Clearata.in>
5. Book – Mukesh Trehan, TR.Jain
6. RBI Site.

